



OIL, EIL to bid for acquiring BPCL stake in NRL

Oil India Limited (OIL) in consortium with Engineers India Limited (EIL) has decided to bid for acquiring 61.65% stake of Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) in Numaligarh Refinery Limited (NRL). The bid is to be submitted through a formal process. The exact percentage of the stake of OIL and EIL will depend on the extent of Right of First Offer (ROFO) to be exercised by Government of Assam which already holds 12.35% stakes in NRL. NRL is the largest customer of OIL's crude produced from its North Eastern fields.

No immediate plans to bring fuel under GST ambit

Many states unlikely to agree due to the impact on VAT revenues

ANURADHA SHUKLA @ New Delhi

THE finance Ministry is not planning to bring petrol and diesel under the ambit of GST in the near future, even though some states and economists have asked for the move to give some relief to consumers.

"There is no such proposal or even formal discussion to bring petrol and diesel under GST, at least in the immediate future. There is a huge revenue implication attached to it and, even when all the states agree to it, it will take several meetings and deliberations to do so," a senior finance ministry official told this publication. The official was clarifying on a statement by West Bengal finance minister Amit Mitra, who had said that many states are open to bringing petrol and diesel under GST, and that it was the Centre that has to do it.

Meanwhile, Finance Minister Nirmala Sitharaman has said that the decision to bring the fuels under GST will have

INDIANS AMONG MOST TAXED FUEL CONSUMERS

While the basic price of petrol is ₹31.82 per litre in Delhi, there is also a central excise of ₹32.90 per litre and a value-added tax of ₹20.61. The basic rate of diesel in Delhi is ₹33.46 per litre, but total tax charged on it adds another ₹43.48 per litre, with excise of ₹31.80 and VAT of ₹11.68

to be taken by the GST Council. "Whenever the GST Council decides to take up this issue, they are well within their interest to take it up and discuss. It's a call which the Council has to take," she had said on Friday.

However, the official added that more than the Centre, many states are not likely to agree to the move since the VAT levied on the fuel is a major source of state government revenue. According to a recent SBI Eco-survey report, petrol prices can go down to ₹75 a litre and diesel to under ₹68 per litre across India if fuel is brought under the ambit of GST. The report blamed the problem on a lack of political will.

"Centre and states are loathe to bring crude oil products under the GST regime as sales

tax/VAT (value added tax) on petroleum products is a major source of own tax revenue for them. Thus, there is lack of political will to bring crude under the ambit of GST," the SBI report authored by Soumya Kanti Ghosh, Group Chief Economic Adviser, SBI, said.

Petrol prices are currently hovering between ₹90-100 per litre across the country. While the basic price of petrol is ₹31.82 per litre in Delhi, there is also a central excise of ₹32.90 per litre and a value-added tax of ₹20.61 taking the total tax portion to ₹53.51 per litre. Similarly, the basic rate of diesel in Delhi is ₹33.46 per litre, but total tax charged on it adds another ₹43.48 per litre, with excise of ₹31.80 and value-added tax of ₹11.68 per litre.

पेट्रोल की कीमतें बढ़ीं, तो बढ़ने लगीं सीएनजी की गाड़ियां

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि के साथ ही दिल्ली में सीएनजी से चलने वाली कारों की तादाद लगातार बढ़ती ही रही है। लॉकडाउन से पहले के मुकाबले अब हर महीने सीएनजी गाड़ियों के बढ़े में शामिल होने वाले वाहनों की तादाद दोगुणा से भी अधिक हो गई है। इसकी एक वजह यह भी मानी जा रही है कि पेट्रोल के दाम बढ़ने के बाद अब सीएनजी और पेट्रोल के दामों में लगभग 55 पैसे का अंतर आ गया है।

दिल्ली और एनसीआर में सीएनजी सप्लाई करने वाली कंपनी इंड्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के सूत्रों का कहना है कि लॉकडाउन से पहले दिल्ली में हर महीने सीएनजी से चलने वाली गाड़ियों की संख्या में 4 हजार की वृद्धि होती रही थी, लेकिन अब यह आंकड़ा दोगुणा से भी अधिक होकर औसतन 10 हजार गाड़ियों का हो गया है। इनमें सीएनजी पर आने वाली नई कारें और सीएनजी किट लगवाने वाली पुरानी कारें दोनों ही शामिल हैं।

अधिकारियों का कहना है कि हाल के कुछ महीनों में जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, उसके बाद सीएनजी की डिमांड में भी वृद्धि नजर आ रही है। एक वजह यह भी है कि हाल ही में कई कार कंपनियों ने सीएनजी के मॉडल बाजार में उतारे हैं।

इंटरस्टे बसें भी सीएनजी से : सूत्रों का कहना है कि आने वाले दिनों में अंतरराज्यीय रूटों पर भी सीएनजी बसों की संख्या में वृद्धि होने की उम्मीद है। अब



तक दिल्ली से बाहर सीएनजी के सीमित स्टेशनों की वजह से लंबी दूरी की बसें डीजल से ही चल रही थीं, लेकिन हाल ही में बसों में सीएनजी के लिए लोहे के परंपरागत सिलेंडर की बजाय फाइबर ग्लास के प्लास्टिक लेयर वाले सीएनजी सिलेंडर का प्रयोग शुरू किया गया है। ये सिलेंडर, लोहे के सिलेंडर के मुकाबले हल्के हैं और इस वजह से बसों में अधिक सिलेंडर लगाए जा सकते हैं।

हाल ही में उत्तराखंड रोडवेज की ओर से दिल्ली देहरादून के बीच एसी 5 बसें चलाई गई हैं। इन बसों में लगे सिलेंडरों में एक बार में 200 किलो सीएनजी भरी जा सकती है। जिससे ये एक बार में एक हजार किमी तक चल सकती हैं। उत्तराखंड रोडवेज के अधिकारी के मुताबिक दो महीने पहले शुरू की गई इस बस सर्विस कामयाब रही है। पहले डीजल से इन बसों में फ्यूल कॉस्ट औसतन 13.39 रुपये किमी आ रही थी, जबकि अब सीएनजी से इसकी लागत 7.11 रुपये प्रति किमी रह गई है।

सीएनजी गाड़ियां बन रही हैं सहारा

- पेट्रोल-डीजल के बढ़ रहे दामों को माना जा रहा है मुख्य वजह
- एक वजह यह भी है कि हाल ही में कई कार कंपनियों ने सीएनजी के मॉडल बाजार में उतारे हैं
- लॉकडाउन से पहले राजधानी में हर महीने सीएनजी गाड़ियों की संख्या में 4 हजार की वृद्धि होती रही थी, अब यह आंकड़ा दोगुने से भी अधिक हो गया है

सी.बी.जी. प्रोजेक्ट्स के लिए पेडा और पेट्रोनेट एल.एन.जी. लिमि. ने साइन किया एम.ओ.यू.

चंडीगढ़, 6 मार्च (बी.एन. 177/3): न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सिज विभाग, पंजाब सरकार के तहत आने वाली पंजाब एनर्जी डिवैल्पमेंट एजेंसी



(पेडा) ने मैस पेट्रोनेट एल.एन.जी. लिमिटेड के माध्यम से पंजाब राज्य में धान की पराली आधारित कम्प्रेस्ड बायोगैस (सी.बी.जी.) उत्पादों के निर्माण में सहयोग करने के लिए भारत सरकार के उद्यम मैस पेट्रोनेट एल.एन.जी. लिमिटेड, नई दिल्ली के साथ एक एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किए हैं। पहले चरण में कम्पनी ने जिला अमृतसर और बठिंडा में 2 प्रोजेक्ट स्थापित करने की योजना बनाई है जिनमें प्रत्येक की क्षमता 12 टन सी.बी.जी. प्रतिदिन होगी।

इस अवसर पर पेडा के सी.ई.ओ. नवजोत पाल सिंह रंधावा, आई.ए.एस.

ने बताया कि भारत सरकार का नव एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एम.एन.आर.ई.) ऐसे सभी प्रोजेक्टों को प्रोत्साहन दे रहा है, जिनमें नई तकनीक का इस्तेमाल करते हुए कृषि कचरे से ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए पेडा पंजाब में पहले से ही कम्प्रेस्ड बायोगैस (सी.बी.जी.) प्रोजेक्टों को बढ़ावा दे रहा है। निजी डिवैल्पमेंट्स को 196 टन सी.बी.जी. प्रतिदिन की क्षमता वाले कुल 19 सी.बी.जी. प्रोजेक्ट आबंटित किए गए हैं।